



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 अक्टूबर, 1994/6 कार्तिक, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अक्टूबर, 1994

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए०(४)-1/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 163-के और जेड-ए के खण्ड (2) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 160 और 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और पदावधि के बारे में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित साधारण जानकारी और सार्वजनिक आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाते हैं। सरकार द्वारा उक्त नियम पर उनके प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

यदि इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति, इनके बारे में कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाह तो वह अपने आक्षेप और सुझाव, उक्त नियम अन्वयि के भीतर निर्देशित, प्राचीन विभाग एवं पंचायती राज विभाग को भज सकेगा।

राज्य सरकार उक्त नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उक्त नियम अन्वयि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य चुनाव आयुक्त" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243 जैड-ए के साथ चिठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अधीन नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त अभिप्रेत है;

(2) अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वेतन.—राज्य चुनाव आयुक्त को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन संदर्भ लिया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण की तारीख से पूर्व, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन की गई पूर्व सेवा के विषय में (निःशुल्कता या क्षति पेंशन से अन्यथा) पेंशन प्राप्त कर रहा था या पेंशन का पात्र है, और उसने पेंशन लेने का निर्वाचन किया था, तो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा के लिए उसके वेतन से निम्नलिखित घटाई जाएगी :

(क) उनकी पेंशन की राशि; और

(ख) यदि उसके पद ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के आधार पर उसे देय पेंशन के बदले में पेंशन के भाग की राशि, जिस पर सांराजिकरण मूल्य लिया गया है :

परन्तु यह और कि जब किसी व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में उस समय नियुक्त किया जाता है जबकि वह सरकारी सेवा में हो तो वह अधिवर्षिता की आयु पूरा करने पर सेवा निवृत्त होगा और उसके पश्चात् उसका वेतन पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार कम किया जाएगा।

4. पदार्थाप.—राज्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु वह किसी भी समय राज्यपाल को सम्बोधित करके आने वाले दिनांक से लिख कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

5. अवकाश.—(1) कोई व्यक्ति जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदग्रहण करने की तारीख में पूर्व सरकारी सेवा में था को उसकी पदावधि के दौरान उस सेवा जिम्मे वह ऐसी तारीख से पूर्व सम्पन्नित है को तत्समय प्रभुत्व लागू नियमों के अनुसार अवकाश प्रदान किया जाएगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं और वह ऐसी तारीख को अपने खाते में जमा अवकाश के अग्रनयन का हकदार होगा।

(2) कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को ऐसे नियमों के अधीन अवकाश प्रदान किया जाएगा जो तत्समय हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी को लागू हों।

(3) राज्य चुनाव आयुक्त को अवकाश प्रदान करने, उसे सम्बोधित करने और प्रतिमंडित करने या कम करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।

6. अवकाश के एवज में नगद भुगतान.—राज्य चुनाव आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी को स्वीकार्य अवकाश के एवज में नगद भुगतान के बराबर अवकाश के एवज में नकद-भुगतान का हकदार होगा :

परन्तु जब कोई सेवा निवृत्त व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसने अपनी अर्धवर्षिता के पश्चात्, अवकाश के एवज में नगद भुगतान प्राप्त किया है, तो वह अर्धवर्षिता पर अवकाश के बदले प्राप्त किए गए भुगतान और 240 दिनों के अवकाश के अन्तर का यदि कोई हो, हकदार होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें.—इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, राज्य चुनाव आयुक्त, अवकाश यात्रा रियायत जो हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी को अनुज्ञेय है, भाड़ा मुक्त अर्ध सुसज्जित आवास या इसकी स्थान पर 2,500/- रुपये प्रतिमास, एक वायलिय में और दूसरा आवास स्थान पर दूरभाष सुविधायें, प्रतिमास 400/- रुपये की दर से सरकार भत्ता और निशुल्क वाहन सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा तथा जब वह सरकारी दौरे पर हो तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी को मिलने वाले दैनिक भत्तों की प्राप्त करने के हकदार होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रेणी-I के अधिकारी के समान चिरित्वा सुविधायें भी प्राप्त करने के हकदार होंगे।

8. पुनः नियुक्ति.—राज्य चुनाव आयुक्त, इन नियमों के नियम, 4 में विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

ओ० पी० यादव,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of Government Notification No. PCH-HA (4-1/94, dated 27-10-1994, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th October, 1994

No. PCH-HA (4)-1/94-3115-3395.—In exercise of the powers conferred by section 160 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) read with clause (2) of

article 243-K and 243-ZA of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules regarding the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner and the same are published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under sub-section (3) of section 186 of the Act *ibid* for general information and for inviting public objections and the said rules shall be taken into consideration by the Government after 30 days of their publication;

If any person likely to be affected by these has any objection or suggestion to make with regard to these rules, he may send the same to the Director of Panchayati Raj and Rural Development Department, Nigam Vihar, Shimla-171002 within the above stipulated period;

The objections and suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before the finalisation of the said rules; namely :—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definition.*—(2) In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) “Governor” means the Governor of the State of Himachal Pradesh; and

(c) “State Election Commissioner” means the State Election Commissioner appointed under section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with articles 243-K and 243-ZA of the Constitution of India.

(2) All other words and expressions used in these rules, but not defined herein, shall have the same meanings as are assigned to them in Act.

3. *Salary.*—There shall be paid to the State Election Commissioner a salary which is equal to the salary of a Judge of the High Court:

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in receipt of or, being eligible so to do, had elected to draw a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of a State or under the Government of the Union, this salary in respect of services as the State Election Commissioner shall be reduced :—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that when a person is appointed as State Election Commissioner while in service of the Government shall retire from service on attaining the age of superannuation and thereafter his salary shall be reduced in accordance with the foregoing proviso.

4. *Term of Office.*—The State Election Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes his office:

Provided that he may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

5. *Leave.*—(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in service of Government, may be granted during his tenure of office but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before such date and he shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date.

(2) Any other person who is appointed as the State Election Commissioner may be granted leave in accordance with such rules as are for the time being applicable to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government.

(3) The power to grant or refuse leave to the State Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the Governor.

6. *Leave encashment.*—The State Election Commissioner shall be entitled for leave encashment as admissible to Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government:

Provided that when a retired person is appointed as the State Election Commissioner and has received leave encashment after his superannuation he shall be entitled for the difference, if any, between the leave encashment he received at the superannuation and 240 days.

7. *Other conditions of service.*—Save as otherwise provided in these rules, the State Election Commissioner shall also be entitled for Leave Travel Concession as per entitlement of a Grade-I Officer of the State Government, rent free semi-furnished accommodation or Rs. 2,500/- per month in lieu thereof, telephone facilities one in the office and another at residence, sumptuary allowance @ 400/- per month and free conveyance facilities and while on official tour entitled to get daily allowance as is admissible to Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government.

8. *Re-appointment.*—The State Election Commissioner shall not be eligible for re-appointment on the expiry of the term specified in rule 4 of these rules.

By order,

O. P. YADAV,

Agri. Pro. Commissioner-cum-Secretary.